नोएडा में फिर भड़का मजदूरों का प्रदर्शन

पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, सेक्टर-80 में हिंसा, मजदूरों का बवाल

नोएडा, 14 अप्रैल. नोएडा सेक्टर 80 में एक बार फिर श्रमिकों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. सोमवार को हुई झड़पों के बाद पहले से सतर्क पुलिस ने मंगलवार को तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया.

इस दौरान कुछ श्रमिकों द्वारा पुलिस पर पत्थरबाजी की भी खबर सामने आई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया.यह विरोध ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

श्रमिकों को खुशखबरी- वेतन बढ़ोतरी का ऐलान

नोएडा. नोएडा और गाजियाबाद में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार की हाई पावर्ड कमेटी ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है. नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी. इसके तहत नॉन-स्किल्ड श्रमिकों को अब 13,690 रुपये, सेमी-स्किल्ड श्रमिकों को 15,059 रुपये और स्किल्ड श्रमिकों को 16,868 रुपये मासिक वेतन मिलेगा.

फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. यह पूरा घटनाक्रम हाल ही में घोषित न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी के बावजूद सामने आया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल मजदूरों की मासिक मजदूरी 11,313 रुपये से बढ़ाकर 13,690 रुपये कर दी है. 15,059 रुपये और कुशल मजदूरों को 16,868 रुपये प्रति माह दिए जाने का प्रावधान किया गया है. अन्य नगर निगम क्षेत्रों और जिलों में भी अलग-अलग श्रेणियों के लिए वेतन में वृद्धि की गई है.

आयकर विभाग ने 'फॉर्म 141' किया शुरू

नई दिल्ली. इनकम टैक्स विभाग ने फॉर्म 141 को शुरू किया है. यह एक कंसोलिडेटेड चालान-कम-स्टेटमेंट है, जो कि चार अलग-अलग टीडीएस फॉर्म का स्थान लेगा. यह नया फॉर्म, फॉर्म 26क्यूबी, फॉर्म 26क्यूसी, फॉर्म 26क्यूडी और फॉर्म 26क्यूई को मिलाकर बनाया है, जिनका उपयोग पहले क्रमश: संपत्ति की खरीद पर टीडीएस, किराए पर टीडीएस, ठेकेदारों या पेशेवरों को किए गए भुगतान पर टीडीएस और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के हस्तांतरण पर टीडीएस दाखिल करने के लिए किया जाता था. नए संशोधित नियमों के मुताबिक, फॉर्म 141 का उपयोग अब 50 हजार प्रति महीने के भुगतान पर टीडीएस और 50 लाख की संपत्ति की खरीद पर टीडीएस जमा करने के लिए किया जा सकता है.

महिला आरक्षण समय की जरूरत : शाह

नई दिल्ली 14 अप्रैल. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द लागू किये जाने को समय की जरूरत बताते हुए उम्मीद जतायी है कि सभी राजनीतिक दल इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे.

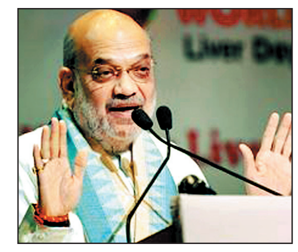

शाह ने महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित विधेयक के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश की नारी शक्ति को मंगलवार लिखे गये पत्र को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इस पर प्रतिक्रिया करते हुए यह बात कही है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक समय की आवश्यकता है। यह हमारी नारी शक्ति का उचित अधिकार है कि वे नीति निर्माण में योगदान दें और राष्ट्र को सशक्त बनाएं. मोदी सरकार इस विधेयक को लाने और लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो निश्चित रूप से बेहतर के लिए बिना किसी देरी के होना चाहिए।मुझे आशा है कि सभी लोग आगे आएंगे और इस ऐतिहासिक कदम का समर्थन करेंगे. उल्लेखनीय है कि श्री मोदी ने विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए संसद में गुरुवार को लाये जाने वाले संशोधन विधेयक से पहले नारी शक्ति को लिखे पत्र में कहा है कि यह भारत की नारी शक्ति के नाम मेरा पत्र है, जिसमें हम दशकों से लंबित इस कार्य को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहे हैं. अपने संदेश में श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया और नीतिगत उपायों तथा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर सरकार के ध्यान को रेखांकित किया है. उल्लेखनीय है कि सरकार विधायिका में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने के लिए इस में संशोधन के लिए गुरुवार को संसद में विधेयक लाने जा रही है.

वेलफेयर एसो. ने मनाया स्थापना दिवस

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना 8वां स्थापना दिवस एवं वार्षिक आम बैठक आयोजित कर कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.

कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के अधिकारों, पारदर्शिता और कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की.इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष मुकेश चौबे, मीडिया प्रभारी बृजेन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरुण व्यास, उपाध्यक्ष प्रशांत पंत, सचिव रमन अरोड़ा, संयुक्त सचिव जितेंद्र नागर, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, संयुक्त कोषाध्यक्ष योगेश कुमार सहित कार्यकारी समिति के सदस्य— अनिल चौधरी, पूजा मेहरा, रोहित यादव, भावना मीना एवं प्रयशी पांडेय उपस्थित रहे.मीडिया प्रभारी बृजेन्द्र सिंह ने संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेवा का उद्देश्य इंजीनियरों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा रेलवे में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से सतत एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना है। बीमा राशि पर जताई नाराजगी हाल ही में एक वरिष्ठ कर्मचारी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए वर्तमान 5 लाख की बीमा राशि को अपर्याप्त बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई. वर्तमान महंगाई के हिसाब से अव्यावहारिक है.

50 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में विनेश चंदेल 10 दिनों की हिरासत में

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 50 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में सोमवार देर रात गिरफ्तार किए गए इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आईपैक) के निदेशक विनेश चंदेल को 10 दिनों की हिरासत में ले लिया है. चंदेल इस कंपनी के संस्थापक, निदेशक और 33 प्रतिशत के शेयरधारक हैं.ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच शुरू की थी.जांच में अब तक आईपैक द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के कई मामले सामने आए हैं.

सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान

अंबेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की : मोदी

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की.

बिरला ने डॉ. अम्बेडकर के प्रमुख योगदानों का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान में समानता का अधिकार तथा बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार जैसे प्रगतिशील प्रावधानों ने एक सशक्त भारत की नींव रखी, जो न केवल भारत के लोकतंत्र को बल्कि विश्व के अन्य लोकतंत्रों को भी निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। भारत के युवाओं को बाबासाहेब के विचारों का सच्चा प्रतिनिधि बताते हुए उन्होंने उन्हें सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया.

अंबेडकर जयंती पर राहुल और प्रियंका गांधी का संदेश

नई दिल्ली. नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ अंबेडकर ने भारत को केवल संविधान ही नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान पर आधारित एक मजबूत राष्ट्र का सपना भी दिया. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में आरोप लगाया कि आज कुछ ताकतें सुनियोजित तरीके से बाबासाहेब की विरासत और संविधान को कमजोर करने में लगी हैं. लोकतांत्रिक संस्थाओं को खोखला किया जा रहा है.

अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है सरकार की योजनाएं : नितिन

नई दिल्ली.भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को कहा कि सरकार की योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है और इसी का अनुकरण करते हुए केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जा रही है. नितिन ने आज यहां भाजपा मुख्यालय में संविधान के शिल्पकार डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलित अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

आज का इतिहास

- 1817- अमेरिका में पहला स्कूल बधिर बच्चों के लिए खोला गया.
- 1820- वुर्टेमबर्ग के राजा विलियम-अपने चचेरे भाई पॉलिन थेरेसे से स्टटगार्ट में शादी की.1840-किंग्स कॉलेज अस्पताल लंदन में खुला.
- 1847- लॉरेंस स्कूल सानवार की स्थापना की गयी.
- 1877- टोक्यो विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पर जापान में स्थापित किया गया.
- 1892- जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क में स्थापित की गयी.

देहरादून एक्सप्रेस से विकास को मिलेगी गति

देहरादून के बीच की दूरी 8 घंटे से घटकर 6 घंटे की : गडकरी

देहरादून, 14 अप्रैल. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण देश के विकास का प्रतीक है और इससे राष्ट्रीय राजधानी तथा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच की दूरी आठ घंटे से घटकर महज छह घंटे की रह जाएगी.

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इस परियोजना में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और वन्यजीवों की आवाजाही को विशेष महत्व दिया गया है ताकि विकास की गतिविधियों से वन्य जीवों की स्वच्छंदता बाधित नहीं हो. वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र में एक्सप्रेसवे को एलिवेटर से जोड़ा गया है वन्य जीव जंतु आसानी से और स्वच्छंदता के साथ विचरण कर सकें.

जाम की स्थिति से निपटने के लिए परियोजना को मंजूरी

देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार में जाम की स्थिति से निपटने के लिए भी परियोजना को मंजूरी दी गई है और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा.हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश के बीच लोगों को जाम के संकट से छुटकारा मिले और आवाजाही को आसान बनाया जाय इसके लिए बेहतर और चौड़ी सड़कों के निर्माण के साथ ही विकास की नयी नयी योजनाओं को पूरा किया जा रहा है.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तराखंड में विकास को नया आयाम मिलेगा. 12000 करोड़ की लागत से निर्मित इस परियोजना से उत्तराखंड में यातायात सुविधा अत्यंत आधुनिक हो जाएगी.

चीन में 72 हजार करोड़ का गुनाह कबूला

बीजिंग, 14 अप्रैल. चीन के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक एवरग्रैंड ग्रुप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है.

समूह के संस्थापक और कभी एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल रहे हुई का-यान ने अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उन पर सार्वजनिक जमा की अवैध वसूली और बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं. यह घोटाला लगभग 72,000 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है, जिसने चीन के रियल एस्टेट सेक्टर को गहरे संकट में धकेल दिया। एवरग्रैंड की मुख्य इकाई हेंगडा रियल एस्टेट के खातों में हेरफेर कर बड़े स्तर पर फंड की गड़बड़ी की गई, जिससे निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ.

सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार का पालन करना अनिवार्य

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा है कि अगर सेवा नियमों में अनुभव, योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर छूट का प्रावधान है, तो किसी कर्मचारी को केवल डिग्री न होने की वजह से प्रमोशन से वंचित नहीं किया जा सकता.

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक सहकारी समिति के कर्मचारी को पदोन्नति देने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने माना कि जब अन्य कर्मचारियों को समान छूट दी गई, तो इस मामले में शैक्षिक योग्यता में रियायत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि भेदभाव अन्याय का ही दूसरा नाम है. अदालत ने जोर दिया कि सरकारी नौकरियों में समानता के अधिकार का पालन करना अनिवार्य है. न्यायालय ने यह टिप्पणी एक प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के कर्मचारी से जुड़े मामले के दौरान की, जिसने लगभग तीन दशकों तक सेवा की थी.

राहुल ने नोएडा में वेतन बढ़ाने के श्रमिक आंदोलन को सही ठहराया

नई दिल्ली, 14 अप्रैल. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोएडा में श्रमिकों के वेतन बढ़ाने को लेकर किए गए आंदोलन को सही ठहराते हुए कहा है कि आसमान छूती महंगाई के साथ मजदूरी बढ़ाने की बात वाजिब है और उनकी इस मांग पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए.

गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर नोएडा में कल कई कंपनियों में श्रमिकों द्वारा वेतन बढ़ाने के लिए किए आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार उनकी न्यूनतम मजदूरी भी बढ़नी चाहिए.कांग्रेस नेता ने कहा कि कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ, वह इस देश के श्रमिकों की आखिरी पुकार थी—जिसकी हर आवाज़ को अनसुना किया गया, जो मांगते-मांगते थक गया.नोएडा में काम करने वाले एक मजदूर की 12,000 रुपये मासिक आय में से 4,000-7,000 रुपये किराए में चले जाते हैं. जब तक 300 रुपये की सालाना बढ़ोतरी मिलती है, मकान मालिक 500 रुपये सालाना किराया बढ़ा देता है.

तमिलनाडु में भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी

परिवार की महिला मुखियाओं को 2000 रुपये

ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 की आर्थिक मदद

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव

चेन्नई, 14 अप्रैल. तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (अन्ना द्रमुक) की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया.

भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र में कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की गयी, जिनमें से कुछ अहम योजनाएं वैसी ही हैं जैसी सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने पेश की थीं। भाजपा ने हर परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये और हर परिवार को एक बार में 10,000 रुपये की नकद सहायता देने का वादा किया है, ताकि महंगाई के दबाव से राहत मिल सके। इसके अलावा, पार्टी ने साल में तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। पार्टी ने योग्य महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपये की आर्थिक मदद देने का भी संकल्प लिया है।

एक ओर जहां द्रमुक ने राज्य की 1.31 करोड़ महिलाओं को दी जाने वाली मौजूदा 1,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का आश्वासन दिया है, वहीं अन्ना द्रमुक ने भी अपने घोषणापत्र में इस राशि को बढ़ाकर 2,000 रुपये करने की घोषणा की है। इसके अलावा, अन्ना द्रमुक ने अभी केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को पुरुषों के लिए भी शुरू करने का वादा किया है.

ईसीआई ने 727 .58 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की

चेन्नई. निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के उड़न दस्ते और सर्विलांस टीम के अधिकारियों ने तमिलनाडु में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखते हुए 727.58 करोड़ रुपये की नकदी एवं अन्य सामग्री ज़ब्त की है, जिसमें शराब और ज्वैलरी भी शामिल हैं.

तमिलनाडु में 234 सदस्यों वाली 17वीं विधानसभा के लिए 23 अप्रैल को चुनाव होने हैं.मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक ने मंगलवार को कहा कि चुनाव कराने में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के लिए, ईसीआई ने चुनावों के लिए 326 पर्यवेक्षक तैनात किए हैं.इनमें 136 सामान्य पर्यवेक्षक, 40 पुलिस पर्यवेक्षक और 151 व्यय लेखा पर्यवेक्षक शामिल थे और उन्हें तमिलनाडु के 234 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया था.केन्द्रीय पर्यवेक्षक के संपर्क विवरण की जानकारी संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के ज़रिए दी गई हैं, ताकि नागरिक, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार सीधे चुनाव से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकें या उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकें.उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव खर्च की कड़ी निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि निगरानी और प्रर्वतन टीमें पूरे राज्य में सक्रिय रूप से तैनात हों ताकि नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और दूसरी प्रतिबंधित चीजों सहित गैर-कानूनी प्रलोभन सामग्री पर नज़र रखी जा सके और उन्हें रोका जा सके.इन तेज प्रर्वतन उपायों के नतीजे में 13 अप्रैल तक तमिलनाडु में कुल मिलाकर 727.58 करोड़ रुपये की ज़ब्ती हुई है.इसमें 126.64 करोड़ नकद शामिल है.2.36 करोड़ की शराब, ड्रग्स/नारकोटिक्स 75.48 करोड़ रुपये, कीमती धातु 295.46 करोड़ रुपये और दूसरी चीज़ें और मुफ्त चीज़ें 226.15 करोड़ रुपये हैं.सुश्री अर्चना पटनायक ने कहा कि जब्त की गई कुल रकम में से 381 करोड़ रुपये सही दस्तावेज जमा करने पर बिना किसी परेशानी के जारी कर दिए गए हैं.

बंगाल विस चुनाव में 2,926 उम्मीदवार मैदान में

नयी दिल्ली/कोलकाता. चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है. चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन वापसी की अंतिम तिथि के बाद राज्य में कुल 2,926 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर 1,478 उम्मीदवार और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1,448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि नौ अप्रैल थी, जबकि 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटिनी) और 13 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी.चुनाव कार्यक्रम के तहत दूसरे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा.सभी निर्वाचन क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के तहत उम्मीदवारों की अंतिम सूची सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करेंगे. आयोग ने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारी चुनावी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए नामांकन, जांच और नाम वापसी से जुड़े रिकॉर्ड को सीलबंद पैकेट में सुरक्षित रखेंगे.मतदाताओं की सुविधा के लिए ईसीआई ऐप नेट पर %अपने उम्मीदवार को जानें% की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

बांग्ला-विरोधी के खिलाफ मजबूती जरूरी : ममता

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोला. उन्होंने विपक्षी दल को 'बांग्ला-विरोधी जमींदार' बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा राज्य के लोगों को बांटने और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी रैली का वीडियो साझा करते हुए बीरभूम, पूर्व और पश्चिम बर्धमान तथा बांकुड़ा के मतदाताओं से टीएमसी को चौथी बार सत्ता में लाने की अपील की. ममता ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में जो कुछ भी हासिल हुआ, वह मां-माटी-मानुष की साझी ताकत का नतीजा है।उन्होंने सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि बांग्ला-विरोधी जमींदारों के खिलाफ मजबूत दीवार बनकर खड़ा होना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने भाजपा और अन्य ताकतों पर राज्य को बदनाम करने और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का आरोप लगाया.

राजनीतिक सफर — सम्राट चौधरी का सीएम तक का सफर, खुद बनाई पहचान, 6 साल पहले भाजपा में आए थे

पिता से सियासी समझ सम्राट को बिहार की कमान

पटना, 14 अप्रैल. सम्राट चौधरी जिनका मूल नाम राकेश कुमार है, बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा. 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी वर्तमान में नतीश कुमार की सरकार में उपमुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत हैं.

उनका राजनीतिक सफर न केवल व्यक्तिगत संघर्ष की कहानी है, बल्कि एक सशक्त राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का उदाहरण भी है.

सम्राट चौधरी, बिहार के दिग्गज नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जिन्होंने राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई थी।इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए सम्राट ने भी राजनीति में अपनी जगह बनाई, लेकिन उनका सफर आसान नहीं रहा.

1990 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने वाले सम्राट ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी.

समय के साथ उन्होंने कई राजनीतिक दलों का रुख किया और अंतत: भारतीय जनता पार्टी में 6 साल पहले शामिल होकर अपने राजनीतिक करियर को नई दिशा दी.

शकुनी चौधरी लालू प्रसाद के केबिनेट मंत्री भी रहे हैं।जार्ज फेर्नांडिस के करीबी सहयोगी रहे।सम्राट की मां पार्वती देवी भी सक्रिय राजनीति में रही हैं और 1998 में तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुकी हैं।परिवार का यह मजबूत राजनीतिक आधार सम्राट के करियर में एक अहम कारक रहा। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी ममता कुमारी हैं और उनके दो बच्चे हैं—प्रणय चौधरी और चारू प्रिया। उनके परिवार में कुल पांच भाई-बहन हैं.